



2026:AHC:164377

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 35/2026

अमित कुमार

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विरोधीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता : राजीव कुमार सक्सेना

विरोधीगण के अधिवक्ता : जी.ए., वीरेंद्र कुमार यादव

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार यादव सूचक के विद्वान अधिवक्ता और श्री नीरज कुमार शर्मा, राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 80/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 105, 127(4), 238(ख) के तहत, पुलिस स्टेशन - अयाना, जिला - औरैया में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। सूचक ने इससे पहले 30.06.2024 को आवेदक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



366, 504, 506, 352 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 0302/2024 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। उक्त मामले में पीड़िता, जो सूचक की बेटा है, ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा कि वह गुस्से में स्वेच्छा से अपने मायके को छोड़ दी थी और फरीदाबाद चली गई थी, उसके माता-पिता ने झूठा मामला दर्ज कराया था। उपर्युक्त कथन के आधार पर पुलिस द्वारा आवेदक के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। आगे यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक ने बाद में पीड़िता से शादी कर ली थी। गर्भावस्था के दौरान उसे चिकित्सीय जटिलताएँ विकसित हुईं और उसे 08.07.2025 को इटावा में भर्ती कराया गया। चिकित्सा उपचार के बावजूद 19.07.2025 को उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं देखी गई। मृत्यु का कारण सेप्टिक शॉक के कारण सेप्टीसीमिया है। यह तर्क दिया जाता है कि स्वतंत्र गवाहों, अर्थात् बलदूराम पाल, शंकर दयाल, हेतराम निषाद और भरत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयानों में यह भी कहा था कि पीड़िता गर्भावस्था में थी। उसकी मृत्यु सेप्टीसीमिया के कारण हुई। उसके परिवार के सदस्यों ने कभी उसकी परवाह नहीं की। हालांकि, मृत्यु के बाद, उन्होंने दूसरों के कहने पर, आवेदक के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और निराधार आरोप लगाने की बात कही। आगे यह तर्क दिया जाता है कि इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक सबूत नहीं है। आवेदक 23.07.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर बढ़ाया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. राज्य के विद्वान एजीए और सूचक के अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन अभिलेख से उपरोक्त प्रस्तुतियों पर संतोषजनक ढंग से विवाद नहीं कर सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, जांच के समय मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं देखी गई थी। मृत्यु का कारण सेप्टिक शॉक के कारण सेप्टीसीमिया है। स्वतंत्र गवाहों बलदूराम पाल, शंकर दयाल, हेतराम निषाद और भरत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयानों में कहा था कि पीड़िता गर्भवती थी। सेप्टीसीमिया के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार के सदस्यों ने कभी उसकी परवाह नहीं की। हालांकि, मृत्यु के बाद, उन्होंने दूसरों के कहने पर, आवेदक के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और निराधार आरोप लगाने की बात कही। इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक वर्तमान में एक वर्ष से अधिक समय तक कैद में है और मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर जब राज्य द्वारा कोई उचित आशंका सामने नहीं लाई गई है कि आवेदक, यदि जमानत पर बढ़ाया जाता है तो या तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या गवाह को डराएगा, मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर बढ़े जाने का हकदार है।

6. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक, **अमित कुमार** को निम्नलिखित शर्तों पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:

- i. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा;
- iii. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

05.08.2026

अभिषेक

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”